बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 149 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 27 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

राष्ट्रपति मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को मार्कापुरम जिले में एक निजी बस के ट्रक से टकराने के बाद उसमें आग लग गई जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। मार्कापुरम के पुलिस अधीक्षक वी हर्षवर्धन राजू ने कहा कि यात्री जलते हुए वाहन के अंदर फंस गए थे। मुर्मू ने एक्स पर कहा, आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में हुई बस दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

राहुल बोले-केरल की नर्स ने रातभर मेरी मां को संभाला, सभा में कहा- नर्सें ही यहां की पहचान; राय में 5 लाख नर्सें; 9 अप्रैल को चुनाव

नई दिल्ली । राहुल गांधी ने एक सभा में सोनिया गांधी की देखभाल कर रही केरल की नर्स का ज़िक्र किया और इन्हें राय की पहचान बताया। दरअसल बुधवार को राहुल को कोझिकोड जाना था, लेकिन वे सोनिया गांधी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से जा नहीं पाए। उन्होंने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। राहुल ने कहा, 'मैं हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था। मैं भी हर बेटे की तरह अपनी मां की सेहत को लेकर बहुत परेशान हूं। हालांकि केरल की नर्स ने मेरी मां का बहुत ख्याल रखा, जिससे उन्हें राहत मिली।' सिर्फ केरल की बात करें तो राय में करीब 5 लाख नर्सें रजिस्टर्ड हैं। वहीं देशभर में केरल की 10 लाख से यादा नर्सें काम करती हैं। वहीं, विदेश में यह संख्या 20 लाख से यादा है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल ने नर्सों का जिक्र कर इस तबके को साधने की कोशिश की है। केरल में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में विधानसभा चुनाव होने हैं। कल रात, मैं हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था। जैसे कि कोई भी बेटा अपनी मां की सेहत को लेकर परेशान रहता है, मैं भी परेशान था।

पूरी रात, मुझे सिर्फ एक चीज से सुकून मिला। मुझे केरल की एक नर्स से सुकून मिला जो हर घंटे मेरी मां को देखने आती थी। हर एक घंटे, वह आकर उन्हें देखती थी। वह मुस्कुराती थी और उनका हाथ पकड़ती थी। मैंने सोचा कि केरल की नर्सों ने कितने बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों को उनके सबसे मुश्किल पलों में सुकून दिया है। सुबह-सुबह, मैंने उनसे पूछा, क्या आप रात में सोती हैं, या पूरी रात काम करती हैं? उन्होंने कहा, मैं पूरी रात काम करती हूं। तो, जब पूरी दुनिया सो रही है, केरल की औरतें, सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि दिल्ली में, पूरे देश में और दुनियाभर में लोगों को सुकून दे रही हैं। उनका हाथ थाम रही हैं, और उन्हें आराम महसूस करा रही हैं। मेरे लिए, यही केरल की पहचान है। फिर केरल चुनाव पर बोले- मोदी जी ने नेशनल लेवल पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था।

केरल के मुख्यमंत्री ने राय में 40 लाख नौकरियों का वादा किया था। 10 साल बीत गए उन्होंने लोगों को एक भी नौकरी नहीं दी है। असल में, उन्होंने नौकरियां खत्म कर दी हैं। न तो बीजेपी और न ही LDF को लगता है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें नहीं लगता कि केरल के लोगों को उनसे सवाल पूछने का हक है। देशभर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसे मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत बताया। महिलाओं के लिए फ्री KSRTC बस यात्रा और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए फाइनेंशियल मदद के तौर पर हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। वेलफेयर पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए के कवरेज के साथ ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, युवाओं के लिए पांच लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन और सीनियर सिटिजन के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाएगा।

अस्पताल ने कहा- सोनिया की हालत स्थिर

सर गंगा राम हॉस्पिटल प्रबंधन ने गुरुवार को बताया कि सोनिया की हालत स्थिर है। वे पिछले दो दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें पेट और यूरिनरी इंफेक्शन के चलते मंगलवार रात 10:22 बजे भर्ती कराया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहे।

183 इंडेन सिलेंडर के साथ अवैध रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली (ए.के.चौधरी)राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में क्राइम ब्रांच (ANTF) ने अवैध एलपीजी रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुल 183 इंडेन LPG सिलेंडर बरामद किए हैं, जो अवैध तरीके से भरे और सप्लाई किए जा रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कई गोदामों में अवैध रिफिलिंग सेटअप चला रहे थे। ये लोग घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर उसे व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ऊंचे दामों पर बेच रहे थे, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा था बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और BNS के तहत बाउंड डाउन किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध गैस सप्लाई कर रहा था। यह सफल ऑपरेशन इंस्पेक्टर महिपाल सिंह के नेतृत्व में, एसीपी सतेंद्र मोहन के निर्देशन और डीसीपी राहुल अलवाल की निगरानी में अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई को जन सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की अवैध रिफिलिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था।

गैस सप्लाई पर सियासत में उबाल, बीजेपी ने विरोधी दलों पर लगाया राष्ट्र विरोधी राजनीति का आरोप

नई दिल्ली । दिल्ली में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर लगातार ओछी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने इसे एक तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि के समान बताया और कहा कि ऐसे बयान देशहित में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि गैस और तेल की कमी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका और कई विकसित देशों तक में इसका असर देखा जा रहा है. इसके बावजूद भारत में विपक्ष इस स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि खाड़ी युद्ध के चलते दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की कमी देखने को मिल रही है. इसके बावजूद भारत सरकार ने शुरुआत से ही प्रभावी नीतिगत कदम उठाए हैं, जिससे इस संकट का असर सीमित रहा है.

दयालपुर में 16 साल के लड़के को चाकू मारने वाले तीनों आरोपी नाबालिग, 13 साल का बचा भी था शामिल!

नई दिल्ली ।

नार्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर इलाके में 16 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जिनपर आरोप है कि उन्होंने मिलकर लड़के को चाकू मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि झगड़े की वजह आपसी रंजिश और बुलिंग थी. दरअसल, पुलिस के मुताबिक 25 मार्च 2026 को दयालपुर थाने में एक लड़के को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां करीब 16 साल का लड़का गंभीर हालत में बेहोश पड़ा था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पता चला कि लड़के पर तीन लोगों ने चाकू से हमला किया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना कर अहम सबूत जुटाए. मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर तेजी से काम करते हुए मृतक की पहचान की और आरोपियों तक पहुंच गई. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने 13 से 17 साल के बीच के तीन नाबालिगों को पकड़ लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि मृतक उनमें से एक लड़के को लगातार परेशान यानी बुली करता था, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

आदिवासियों के अधिकार दिलवाने को समर्पित भारतीय आदम जाति सेवक संघ

दिल्ली (इंद्रजीत सिंह) आदमजाति सेवक संघ के 78 वे दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन संस्था के मुख्यालय झंडेवालान में आयोजित किया गया, इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य थे, विशिष्ट अतिथि जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गा दास उइके व महिला बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर व मातृश्री काशीबा गोटी चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख केशुभाई हरिभाई गोटी थे,

कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष, पूर्व न्यायाधीश एवं छहस्त्र के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश कुमार उइके ने की। कार्यक्रम का संचालन महासचिव अजय कुमार चौबे ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए मनमोहक रुप से किया।

अंतर सिंह आर्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यपद्धति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आयोग जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने व सभी को उनके अधिकार आसानी से प्राप्त हो सके यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, दुर्गा दास उइके ने आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आदिवासियों आज भी प्राकृतिक के महत्व को जिन्दा रखने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीमती सावित्री ठाकुर ने अपने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओ को विस्तार से बताते हैं कहा कि हमारा प्रयास है कि महिलाओ को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग व आसानी से मिले यह प्रयास कर रहे हैं।

गुजरात के मातृश्री काशीबा गोटी चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख व हीरा व्यापारी केशुभाई हरिभाई गोटी ने कार्यक्रम में आए सभी से आदिवासियों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास, स्कूल व उनके शिक्षा के सुविधाए उपलब्ध कराने पर बल देते हुए कहा कि उनकी संस्था अब तक 300 से अधिक छात्रावास व स्कूलो का निर्माण करा चुकी है।

संस्था के सचिव राजेश मालवीय ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को संस्था के कार्यों में आने वाली कठिनाई को साझा करते हुए कहा हमें आदिवासियों की कठिनाइयों का कानूनी रूप से हल निकालने के लिए उनमें जागरूकता फैलानी होगी। हमें पेसा एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, वन धन अधिकार की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।

अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रजि के संयोजक राजेंद्र खर्रा ने दिल्ली के आदिवासियों की पीड़ा अतिथियों के सामने रखते हुए कहा कि दिल्ली के आदिवासी आज भी दिल्ली में अपनी पहचान को तरस रहे हैं।

श्रीमती रेणु चारी ने घुमंतू समाज की समस्यायों को उठाते हुए कहा कि घुमंतू समूदाय को जनगणना में उचित स्थान नहीं मिलता, जनजाति मंत्रालय के परियोजना विशेषज्ञ ऋषभ चतुर्वेदी ने जनजाति कार्य मंत्रालय की योजनाओं को हासिल करने के तरीके पर प्रकाश डाला, पुरस्कार फाउंडेशन के निदेशक गौतम कुमार ने संस्थाओं को सरकारी सहायता कैसे प्राप्त होती है इस पर प्रकाश डाला। जनजाति कार्य मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर सुभाष कुमार ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से समस्याएं सुनी और उनके समाधान के रास्ते बताए।

वनवासी कल्याण आश्रम के प्रवीण ढोलकिया ने आदिवासियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें समस्याओं से जूझना पड़ेगा।

कार्यक्रम का समापन करते हुए भारतीय अदमजाति सेवक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश उईके ने सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि इस अधिवेशन में हासिल की गई जानकारी का उपयोग अपने-अपने क्षेत्र में करते हुए आदिवासियों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज, वनवासी कल्याण आश्रम, उड़ीसा की सर्वोदय समिति, तेलंगाना की रानी माता दुर्गावती संस्थान, उत्तर प्रदेश से वनवासी विकास आश्रम, कर्नाटक से मा. आ. से. संघ, सर्वोदय सेवा समिति सहित 57 संस्थाओं के प्रतिनिधित्व ने अधिवेशन में भाग लेकर अपने अपने बहुमूल्य विचार,मार्गदर्शन एवं अनुभव साझा करते हुए जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त किया।

कार्यक्रम में धानका समाज के प्रतिनिधियों में आए हुए अतिथियों को पगड़ी बनाकर सम्मान किया, कार्यक्रम में दिल्ली के कात्यानी आदिवासी छात्रावास, लखीमपुर के आवासीय विद्यालय गोबरौला,कालसी उत्तराखंड आदिवासी की बालिकाओं द्वारा लोकगीतों वे नृत्य से कार्यक्रम में आए लोगों का मनमोह लिया।

इस अवसर पर राहुल सिंह,डा आर एम कुबेरप्पा,कुंवर जितेन्द्र नरसिंह राणा, श्रीमती एला बैन देसाई, सुरेन्द्र कुमार चौहान, प्रदीप महान्ती, भुवनेश शर्मा,जय प्रकाश गुप्ता,मुकुन्द बापट,नून नून भाई मिश्रा, राजकुमार, नत्थू लाल मोरवाल,राजेश देहराण,रेखा सहित अनेक प्रांतों से आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम को सुचारू रूप चलाने व व्यवस्था में भारतीय आदमजाति सेवक संघ के कार्यालय सचिव रविकांत झा, अनिल शर्मा, परदेसी राणा सहित सभी कर्मचारियों ने अहम् भूमिका निभाई।

पाकिस्तानी मुस्लिमों द्वारा सिख महिलाओं का धर्म परिवर्तन

हिन्दू-सिखों का धर्म परिवर्तन भले ही वह जबरन करवाया गया हो या फिर किसी भी तरह के लोभ लालच देकर हो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और खासकर पंजाब में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। इस पर देश के गृह मंत्री भी चिन्तित है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। मगर वहीं विदेशों में पाकिस्तानी मुस्लिमों के द्वारा ग्रूमिंग गैंग के तहत सिख महिलाओं को मुस्लिम बनाने के पीछे "कौर टू खान" मुहिम चलाए जाने की बात सामने आ रही है जो बेहद चिन्ता का विषय है। इसके लिए यह भी जानकारी मिल रही है कि 10 हजार पौंड तक उन महिलाओं को दिए जा रहे हैं जिसके लालच में आकर सिख परिवारों की बच्चियां जो पढ़ने के लिए विदेश गई हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही वह इसके जाल में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करवाती दिख रही है। वैसे तो पिछले दो दशकों में यूनाइटेड किंगडम में बच्चों और युवतियों के शोषण से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आते रहे हैं मगर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसने सिख समुदाय को बेहद चिन्तित कर दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सिख महिलाओं ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया भले ही उन्हें कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, यहां तक कि धर्म परिवर्तन ना करने के चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उनके सामने उनके बच्चों को बेरहमी से शहीद किया गया पर वह अपने धर्म में पक्के रहीं। मगर शायद लगता है कि समय के साथ-साथ आज परिस्थितियां बदली हुई हैं जिसके चलते थोड़े से पैसों के लालच में सिख महिलाएं अपना धर्म छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाती। आज एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक गहरी साजिश के तहत सिख परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में एक मामला पाकिस्तान गुरुद्वारों के लिए जाने वाले जत्थे में देखा गया जिसमें सरबजीत कौर की महिला ने पहले जत्थे से अलग होकर पाकिस्तान के एक मुस्लिम लड़के से निकाह करके धर्म बदला और अब वहां से सिखों के खिलाफ जहर उगल रही है। सिख बुद्धिजीवियों और नेताओं को इसके लिए आगे आकर सिख परिवारों की बच्चियों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक सिख परिवारों की बच्चियां इसके प्रति जागरूक नहीं होंगी ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रचलन सिख परिवारों की लड़कियों का विदेश जाने का रहता है इसलिए वहां जागरूकता अभियान चलाने की अधिक आवश्यकता है। आजकल यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ सिखों के द्वारा मुस्लिम समुदाय से मित्रता बढ़ाने का शौक पैदा हो रहा है उन्हें भी इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोग ग्रूमिंग गैंग के रूप में कार्यरत है उन पर शिकंजा लगवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। वहीं यूके की सरकार को भी जबरन धर्म परिवर्तन या फिर लालच में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करनी चाहिए। हाल के वर्षों में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अभियान को मुख्य रूप से सिख फार जस्टिस नामक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल सिख प्रवासी समुदाय से पैसा और समर्थन निकालने मात्र है। हालांकि भारत सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसके आयोजकों और समर्थकों के कथित तौर पर संगठित अपराध से जुड़े होने के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। यह भी देखा जाता है कि आयोजकों के संगठित अपराध से गहरे संबंध के प्रमाण भी कई बार मिल चुके हैं। दिसंबर 2025 में, कैलिफोर्निया में सिख फार जस्टिस के खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजक जसपाल सिंह को एक हाई स्कूल के बाहर स्टिंग ऑपरेशन में 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान, उसने आरोपों को स्वीकार किया। ऐसी घटनाएं दिखाती है कि "खालिस्तानी समूह" रिको एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो अमेरिका के उन संगठित आपराधिक गिरोहों को निशाना बनाता है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। जनमत संग्रह के नाम पर प्रवासी समुदाय का शोषण करते हुए गंभीर अपराध करना, नेताओं को संघीय अभियोजन के दायरे में लाता है। कई सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत मिले है कि इस प्रकार के जनमत संग्रह के पीछे केवल राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों का एक नेटवर्क भी सक्रिय है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, और हथियारों की आपूर्ति जैसे गंभीर अपराध शामिल बताए जाते हैं। इस तरह के नेटवर्क अक्सर अलगाववादी आंदोलनों को आर्थिक और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं जिन्हें रोकने के लिए हर देश की सरकारों को सख्ती से पेश आना होगा। "खालिस्तान जनमत संग्रह का आयोजन मुख्य रूप से कनाडा, ब्रिटेन, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में किया जाता है। इन देशों में सक्रिय कुछ तत्वों पर आरोप है कि वे स्थानीय कानूनों का लाभ उठाकर भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे है। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को भड़काने और गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। सिख धर्म के पांच तख्त साहिबान है जिनमें सिरमौर श्री अकाल तख्त साहिब है जिसकी स्थापना छठे गुरु हरिगोबिन्द साहिब के द्वारा की गई थी, उसके बाद तख्त श्री पटना साहिब जो कि गुरु गोबिन्द सिंह जी की जन्मस्थली है। इसी प्रकार तख्त सचखण्ड हजूर साहिब नदेड़, तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब और तख्त साहिब श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो भी सुशोभित है। हर सिख की इच्छा रहती है कि वह पांच तख्त साहिबान के दर्शन अपने जीवनकाल में अवश्य करे मगर सीधी रेल सेवा ना होने के चलते कई सिख दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। देश को आजाद हुए आज 79 साल होने को है मगर आज तक किसी भी रेल मंत्री के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित ही नहीं किया गया या यह कहा जाए कि किसी की सोच ही नहीं थी। मगर पंजाब के युवा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को जब से रेल मंत्रालय में बतौर रेल राज्यमंत्री का कार्यभार मिला उनकी पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरह से सिख धर्म के पांच तख्त साहिबान को आपस में रेल सेवा से जोड़ा जाए।

दलदल में ट्रम्प

भारत ने हमेशा युद्ध संकट का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का समर्थन किया है। भारत ने हमेशा समूचे विश्व को शांति का संदेश देते हुए बार-बार कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं, भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ शांतिवार्ता की पहल करने और 5 दिन की युद्ध विराम की घोषणा करने के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन घुमाया और पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज को लेकर चर्चा की। ट्रम्प की इस पहल से स्पष्ट है कि वे पश्चिम एशिया के संकट को सुलझाने के लिए भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देख रहे हैं। शायद ट्रम्प को इस बात का अहसास है कि ईरान के साथ युद्ध विराम को सफल बनाना है और तेल की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखनी है तो भारत की भूमिका सबसे अहम है। ट्रम्प के शांति संकेत देते ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत की थी। उसके बाद ट्रम्प की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत हुई। इस कूटनीतिक टाइमिंग के पीछे भारत ने बहुत ही सतर्कता और सूझबूझ से काम लिया। जब अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को तबाह करने पर आमादा था तब भारत ने वाशिंगटन के सुर में सुर मिलाने से परहेज किया। इसका सीधा कारण यह है कि ईरान के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन कर रहा है, जो मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत का 'गेटवे' है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि भारत युद्ध के चरम पर अमेरिका का खुला समर्थन करता तो क्षेत्र में उसके अपने हित खतरे में पड़ जाते। नई दिल्ली शुरू से ही कूटनीति और संवाद के जरिए तनाव कम करने का पक्षधर रहा है, न कि बमबारी का। इसलिए, जब तक युद्ध के बादल सबसे ज्यादा घने थे, भारत ने पेंटागन की युद्ध नीतियों से खुद को अलग रखा। डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यद्यपि उन्होंने विस्तार से बताने से साफ इंकार किया लेकिन ऐसे संकेत है कि यह तोहफा तेल और गैस से जुड़ा हुआ है। उनके इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है। आखिर यह तोहफा है क्या जिसने अमेरिका को जंग रोकने की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। युद्ध के दौरान कई तरह की बयानबाजी की जाती है, जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। अब सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका में कोई बातचीत चल रही है। यह भी वास्तविकता है कि ट्रम्प युद्ध के दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हैं और वह निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका को रोजाना 1.38 अरब डॉलर खर्च करने पड़ रहे है और 25 दिन की जंग में अमेरिका लगभग 20 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। पैंटागन ने 200 अरब डॉलर से अधिक की राशि और मांगी है। इसे अमेरिकी कांग्रेस यानि संसद से पारित कराना होगा, जिसके पारित होने की उम्मीद कम है। यद्यपि ट्रम्प ने नाटो और यूरोपीय देशों को कायर और कागजी शेर कहा। इसके बावजूद नाटो और सहयोगी देश उनके साथ नहीं आए। किसी ने युद्धपोत नहीं भेजे। कतर में एलएनजी सप्लाई बंद होने से यूरोप में गैस की कीमतें 35 प्रतिशत बढ़ गईं। जापान तक को अपना रणनीतिक भंडार निकालना पड़ा। 9 देशों में 40 ऊर्जा भंडार युद्ध से प्रभावित हुए हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति रोजाना 11 मिलियन बैरल घटी है। 66 प्रतिशत अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ है और ट्रम्प की लोकप्रियता घटी है। ट्रम्प का यूटर्न इस बात का संकेत है कि वह युद्ध रोकने के पक्षधर है लेकिन इजराइल बेलगाम गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। ईरान और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी अपनी मिसाइलों से तेल अवीव से लेकर यरुशलम तक तबाही मचा रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ट्रम्प के बातचीत के दावों को पूरी तरह से नकार रहा है लेकिन ईरान के राष्ट्रपति द्वारा रखी गई शर्तों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कूटनीतिक गलियारों से छन-छन कर जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार ईरान ने भविष्य में आक्रामकता के खिलाफ गारंटी, बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई और ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता शामिल है। ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में एक महीने की ढील दी है। जबकि ईरान का कहना है कि उसके पास अतिरिक्त तेल है ही नहीं तो ढील का कोई मतलब ही नहीं है। यद्यपि तुर्की और मिस्र ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं लेकिन मध्यस्थता के खेल में पाकिस्तान का शामिल होना काफी अखरता है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर उछल-उछलकर बातें कर रहे हैं।

आठ-आठ युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प खुद मध्यस्थ की तलाश में जुटे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही है। ईरान के खिलाफ एक लम्बे और महंगे युद्ध का खतरा, तेल की कीमतों में तेज उछाल, गैस संकट और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों के दबाव के कारण ट्रम्प अब स्वयं कायर दादा के तौर पर छवि बना चुके हैं। किसी भी राजनयिक प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ट्रम्प को पहले अपने सहयोगी इजराइल पर लगाम लगानी होगी। इजराइल द्वारा अपनाया गया सैन्य मार्ग स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं दिखा रहा है।

ट्रम्प के लिए सबसे कम नुकसानदेह रास्ता ईरान के साथ संवाद कायम कर युद्ध से बाहर निकलना ही दिखाई देता है। उम्मीद कायम है कि कूटनीति के द्वार खुलेंगे और पश्चिम एशिया में शांति का माहौल कायम होगा। आने वाले दिनों में भारत भी शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखना होगा बातचीत किस दिशा में जाती है।

सम्पादकीय...

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तलाशने की बढ़ी दरकार

ईरान पर अमेरिकी और इजरायली कार्रवाई के बाद पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को कई तरह की परेशानियों और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खाड़ी संकट जल्द नहीं थमा तो पहले से ही करीब अस्सी अरब डॉलर सालाना खर्च करने वाले भारत की ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। पेट्रोलियम कारोबार पर निगाह रखने वाले वैश्विक संस्थानों को आशंका है कि अगर ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध लंबा खिंचा और इससे कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल दस डॉलर की भी बढ़ोत्तरी हुई तो भारत का पेट्रोलियम आयात खर्च पंद्रह हजार करोड़ डॉलर सालाना बढ़ सकता है। पेट्रोलियम आयात पर होने वाली इस बढ़ोत्तरी के चलते भारत पर नए सिरे से आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर नए सिरे से विचार करे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश की दिशा में ना सिर्फ आगे बढ़े, बल्कि शोध और विकास पर भी जोर लगाए। खाड़ी संकट के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को इस दिशा में सोचने को मजबूर किया है। तमाम देश वैचारिक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्पों की खोज में जुटने लगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दुनिया का बढ़ता ध्यान इसी बदलते सोच का प्रतीक है। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर पिछले कुछ वर्षों में इतना जोर दिया है कि वहां एक तरह से इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति ही आ गई है। भारत ने साल 2030 तक कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ईरान संकट के पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों से सालाना पेट्रोलियम आयात में करीब 25 हजार करोड़ की बचत होने लगी है। लेकिन जिस तरह पेट्रोलियम उत्पादक खाड़ी के क्षेत्र में हालात बदल रहे हैं, उससे देश को पेट्रोलियम के विकल्प ढूंढने की दिशा में तेजी लाने और इस सिलसिले में शोध और विकास को भी गति देने की जरूरत बढ़ी है। ऐसा किए बिना देश के लिए पेट्रोल और डीजल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के भारी खर्च पर लगाम लगाना आसान होगा। भारत के संदर्भ में देखें, तो रसोई गैस के मोर्चे में देश ने पिछले दस वर्षों में बड़ी क्रांति को देखा है। देश के रसोई घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की खपत बढ़ी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में प्राकृतिक गैस की रोजाना खपत करीब 189 मिलियन घन मीटर है। लेकिन घरेलू उत्पादन महज 97.5 मिलियन घन मीटर रोजाना ही है। करीब साठ फीसद गैस बाहर से आयात ही करना पड़ता है। देश में करीब 33 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं। इनमें दस लाख 33 हजार कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। इन कनेक्शनों पर सालाना 312 लाख टन गैस खर्च होती है। इस खर्च होने वाली गैस का साठ फीसद हिस्सा आयात किया जाता है। जाहिर है कि देश का बड़ा गैस खर्च भी आयात पर ही निर्भर है। इसमें दो राय नहीं कि आधुनिक दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ ही है, जिसमें डीजल, पेट्रोल और गैस तीनों ही शामिल हैं।

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था

युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं। इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि उसे हथियारों की दुनिया बनानी है या मानवता की दुनिया। यदि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध नहीं रुके और हथियारों की होड़ इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के बारे में सोचें और युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। मानव सभ्यता का भविष्य हथियारों से नहीं, बल्कि शांति, संवाद और सहयोग से सुरक्षित हो सकता है। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। युद्ध का अंधेरा मानवता को केवल विनाश, महंगाई, भय और अस्थिरता देता है, जबकि दुनिया को आज शांति, संवाद और स्थिरता का उजाला चाहिए, और इस दिशा में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभरा है जो युद्ध नहीं, संवाद-संघर्ष नहीं, सहयोग और हिंसा नहीं, सहअस्तित्व की बात करता है।

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर खड़ी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा-संतुलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान और इजरायल के बीच हमलों का नया दौर, अमेरिका की रणनीतिक भूमिका, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान तनाव जैसे अनेक घटनाक्रम मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन की राजनीति की ओर लौट रही है। यह स्थिति केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का संकेत भी है, क्योंकि जब दुनिया हथियारों पर ज्यादा खर्च करती है तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं। आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वास का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वास ही युद्ध की जमीन तैयार करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह पैसा मानव विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बड़े देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है और पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि वहां युद्ध बढ़ता है या समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः हर वस्तु महंगी हो जाएगी। यानी एक वैश्विक महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है। पहले से ही कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और यदि ऊर्जा संकट बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। भारत जैसे देश भी इस स्थिति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केवल केंद्र सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों को भी इस स्थिति को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया युद्ध को रोकने के बजाय उसकी तैयारी ज्यादा कर रही है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन होता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विराम की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहे तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के साथ वार्ता शुरू करा सकता है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विराम की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है। हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा हिस्सा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और भूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व नेतृत्व यह समझे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है। युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं। इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि उसे हथियारों की दुनिया बनानी है या मानवता की दुनिया। यदि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध नहीं रुके और हथियारों की होड़ इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के बारे में सोचें और युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। मानव सभ्यता का भविष्य हथियारों से नहीं, बल्कि शांति, संवाद और सहयोग से सुरक्षित हो सकता है। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। युद्ध का अंधेरा मानवता को केवल विनाश, महंगाई, भय और अस्थिरता देता है, जबकि दुनिया को आज शांति, संवाद और स्थिरता का उजाला चाहिए, और इस दिशा में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभरा है जो युद्ध नहीं, संवाद-संघर्ष नहीं, सहयोग और हिंसा नहीं, सहअस्तित्व की बात करता है। भारत बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा की परंपरा का देश है, इसलिए भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करे, युद्धरत देशों के बीच संवाद का सेतु बने, संयुक्तराष्ट्र के मंच पर युद्ध विराम की ठोस पहल करे, तो वह विश्व राजनीति को नई दिशा दे सकता है। मोदी यदि शांति, अहिंसा, वैश्विक संवाद और आर्थिक सहयोग के चार सूत्रों पर विश्व को साथ लाने की पहल करें तो भारत वास्तव में विश्व शांति का मार्गदर्शक बन सकता है और युद्ध की दिशा में बढ़ती दुनिया को शांति और स्थिरता की दिशा में मोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभा

ईरान-इज़रायल-अमेरिका युद्ध- जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली, पानी ऊर्जा और आम नागरिकों पर मंडराता वैश्विक संकट

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष,विशेषकर ईरान,इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात ने विश्व व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा और तत्काल प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है।अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, यह संकट 1970 के दशक के तेल संकट के बाद सबसे गंभीर हो सकता है। कई देशों ने बिजली और ईंधन की खपत कोनियंत्रित करने के लिए ऊर्जा इमरजेंसी जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।पाकिस्तान,बांग्लादेश, श्रीलंका फिलीपींस जैसे देशों में बिजली कटौती,पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति और स्कूल बंद करने जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं।आश्चर्यजनक रूप से, यह संकट केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और न्यूजीलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों में भी ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहता हूं कि हर युद्ध की शुरुआत में इसे इंसानियत की रक्षा और शांति की स्थापना के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है।जब ऊर्जा से आगे बढ़कर पानी बना युद्ध का नया हथियार तो यह इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है।अब यह केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पानी जैसे जीवनदायी संसाधन तक पहुंच गया है।खाड़ी देशों में प्राकृतिक मीठे पानी की भारी कमी है और वे समुद्री पानी को शुद्ध करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है।यदि इन संयंत्रों पर हमले होते है, तो स्थिति भयावह हो सकती है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब अपनी लगभग 70 प्रतिशत पेयजल आवश्यकता इन प्लांट्स से पूरी करता है, जबकि कुवैत लगभग 90 प्रतिशत और ओमान 86 प्रतिशत तक निर्भर है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने या संयंत्रों के नष्ट होने पर इन देशों में पानी का संकट तुरंत उत्पन्न हो सकता है।ट्रंप ने भी दावा किया कि यह अभियान ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और वहां के लोगों को तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने के लिए है।दूसरी ओर, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी।लेकिन 26 दिनों के भीतर ही इस युद्ध का स्वरूप बदल गया है।अब सैन्य ठिकानों की बजाय आम नागरिकों के जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी और ऊर्जा पर हमले की धमकियां दी जा रही है। ट्रंप द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की चेतावनीदी थी और उसके जवाब में ईरान द्वारा पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा एवं जल ढांचे को नष्ट करने की धमकी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध का केंद्र जनता बन चुकी है। साथियों बात अगर हम डिसैलिनेशन प्लांट्स पर खतरा- जीवनरेखा पर सीधा हमला इसको समझने की करें तो ईरान द्वारा खाड़ी देशों के प्रमुख जल और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों के प्रमुख प्लांट्स खतरे में हैं।यदि ये संयंत्र नष्ट होते हैं, तो न केवल पीने के पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी, बल्कि बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये दोनों प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस स्थिति में पूरा खाड़ी क्षेत्र प्यास और अंधेरे के संकट में फंस सकता है। साथियों बात अगर हम आम नागरिकों पर असरमानवीय जीवन से जुड़े बुनियादी ढांचे बिजली,पानी ऊर्जा और आम नागरिकों पर मंडराता वैश्विक संकट जीवनशैली में भारी बदलाव इसको समझने की करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई देशों में ईंधन की कमी के कारण स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू कर रही है, और पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सीमाएं तय की जा रही है। बिजली कटौती आम हो गई है, जिससे उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहे हैं।ऊर्जा संकट ने जीवन की बुनियादी जरूरतों रसोई गैस, परिवहन, बिजली और पानी को सीधे प्रभावित किया है। इससे सामाजिक असंतोष और आर्थिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है ठीक वैसे ही,वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा- मंदी की आशंका ऊर्जा संकट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है,जिससे महंगाई बढ़ती है और उपभोक्ता खर्च घटता है।विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। इस युद्ध के कारण लाखों भारतीयों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, और हजारों लोग वापस लौट चुके हैं। साथियों बात कर हम पानी की जंग- भविष्य का सबसे बड़ा खतरा इसको समझने की करें तोविश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष भविष्य में पानी की जंग का संकेत हो सकता है। जिस तरह तेल ने 20वीं सदी में भू-राजनीति को प्रभावित किया, उसी तरह पानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है।यदि जल स्रोतों और जल आपूर्ति प्रणालियों पर हमले बढ़ते हैं, तो यह मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। पानी की कमी न केवल स्वास्थ्य संकट पैदा करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर पलायन, सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकती है। साथियों बात अगर हम ऊर्जा संकट का वैश्विक विस्तार- 1973 जैसा खतरा इसको समझने की करें तो,मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। मध्य पूर्व विश्व के तेल और गैस उत्पादन का केंद्र है, जहां से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन पूरी दुनिया में निर्यात होते हैं। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के उत्पादन केंद्रों पर खतरे के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है।यह स्थिति 1973 के तेल संकट की याद दिलाती है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है,ऊर्जा की कमी,महंगाई में वृद्धि,और वैश्विक मंदी का जोखिम मंडरा रहा है। साथियों बात अगर हम होर्मुज जलडमरूमध्य- वैश्विक आपूर्ति की जीवनरेखा पर संकट,होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है,जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हमलों के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है।भारत सहित एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रही हैं। भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और आर्थिक दबाव के रूप में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। साथियों बात अगर हम युद्ध के बयानों पर नजर डालें तोहर जंग की शुरुआत में एक घोषणा की जाती है- यह जंग इंसानियत को बचाने की जंग है, लाखों जान बचाने के लिए न टाली जा सकने वाली जंग है. ईरान के खिलाफ 26 दिन पहले अमेरिका और इजरायल की तरफ से जब जंग शुरू की गई थी तब भी कुछ ऐसे ही दावे किए गए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान के लोगों को एक तानाशाही शासन से आजादी दिलाने निकले हैं, इस्लामिक शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए निकले हैं. ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए कहा कि वह इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा,हालांकि अब कहानी का प्लॉट ही बदल चुका है।अब नेता नहीं जनता निशाने पर है. ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि उनकी सेना पूरे ईरान के बिजली संयंत्र को निशाने बनाने वाली है, तो वहीं ईरान ने कहा कि कोई भी हमला हुआ तो वह पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा.ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि युद्ध का असली चेहरा और मानवता के लिए चेतावनी,ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह ऊर्जा, पानी और मानव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्धों में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। बिजली, पानी और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें जब युद्ध का हथियार बन जाती हैं, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है।दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अगर समय रहते कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह संकट वैश्विक आपदा का रूप ले सकता है। यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी है कि संसाधनों की लड़ाई भविष्य में कितनी भयावह हो सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैनलैस एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे।

बौद्ध परिपाटी को मिटाने की साजिश का आरोप, आजाद समाज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी

कुशीनगर।

पडरौना, कुशीनगर में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिलाध्यक्ष राहुल चौधरी ने आरोप लगाया है कि जनपद में सरकारी योजनाओं की आड़ में बौद्ध परंपरा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ता इस साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। यह बयान उन्होंने रामाभार स्तूप के निकट स्थित चीना मंदिर के पास नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिया। राहुल चौधरी ने कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर परिसर में स्थित उक्त बुद्ध विहार का निर्माण भंते चीना द्वारा लगभग 18 कट्ठा भूमि खरीदकर कराया गया था, जिसे स्थानीय लोग चीना भंते बुद्ध विहार के नाम से जानते हैं। उनका आरोप है कि इस स्थल को पहले ग्राम समाज की भूमि में शामिल कर सरकारी घोषित किया गया, जबकि किसी मंदिर या बुद्ध विहार को सरकारी नहीं बनाया जा सकता, केवल उसका संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि

वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से चीना बाबा मार्केट के नाम पर आरसीसी निर्माण कराया गया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1958 के अधिनियम के विरुद्ध है। जिलाध्यक्ष के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका परिषद को नोटिस जारी कर कार्य रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। इसके बाद भी विभाग द्वारा दोबारा नोटिस जारी कर निर्माणाधीन स्थल पर चस्पा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा पुरातत्व विभाग के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है, साथ ही बौद्ध अनुयायियों को डराने-धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने 24 मार्च को महापरिनिर्वाण महाविहार के निकट प्रदर्शन किया था, जिसे प्रशासन द्वारा कचरा गाड़ियों को हटाने और निर्माण कार्य रोकने के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अब पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे समझौते का उल्लंघन बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य नहीं रोका गया तो पार्टी फिर से आंदोलन करेगी।

भटनी में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार, गैलन व मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल लेने उमड़े लोग

भटनी देवरिया।

भटनी नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। सुबह से ही मोटरसाइकिलों की लाइन लग जा रही है और कई लोग गैलन लेकर भी पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़भाड़ का माहौल बना हुआ है।

नकहनी भारत पेट्रोल पंप पर थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने संभाली व्यवस्था, लाइन लगवाकर कराया वितरण

नगर के कई पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर पेट्रोल बांटा जा रहा है। अचानक बढ़ी भीड़ के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की कमी की आशंका को देखते हुए लोग पहले से ही पेट्रोल लेने के लिए पंपों पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में नकहनी स्थित भारत पेट्रोल पंप पर पुलिस प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय स्वयं मौके पर मौजूद रहे और लोगों को लाइन में लगवाकर व्यवस्थित तरीके से पेट्रोल वितरण कराते हुए दिखाई दिए। पुलिस की निगरानी में पेट्रोल वितरण शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया, जिससे अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनने पाई।

शांति और अहिंसा का प्रतीक है सम्राट अशोक का जीवन- रामअवध यादव

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामअवध यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट अशोक का जीवन शांति और अहिंसा का प्रतीक है।

कुशीनगर।

पडरौना स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन में महान सम्राट अशोक की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामअवध यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट अशोक का जीवन शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युद्ध जीतने के बाद भी सम्राट अशोक द्वारा सब कुछ त्याग देना उनकी महानता को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष की अगुवाई में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में रामअवध यादव ने कहा कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के तृतीय शासक थे और कलिंग युद्ध में हुई भारी जनहानि को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जो शांति और अहिंसा का संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से प्रेरित है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर लोकतंत्र को बचाने तथा वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम को विजय प्रताप कुशवाहा, विक्रमा यादव, राजेंद्र यादव मुन्ना, मोहम्मद इलियास अंसारी, वीरेंद्र सिंह सैंथवार और अवध नाथ ठाकुराई सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव ऐनुल हक ने किया। इस अवसर पर राजेंद्र पाल, सिकंदर आलम, भोला यादव, चंद्र प्रकाश यादव, अवधेश राय, मनोज कुशवाहा, लल्लन यादव, हीरालाल प्रजापति, अकबर अंसारी, हीरा प्रसाद, बड़े अंसारी, महेश कुशवाहा, फखरुद्दीन अहमद, कपिल देव कुशवाहा, अजहर अहमद, अनिरुद्ध कुशवाहा, धर्मनाथ कुशवाहा, कपिल देव गोंड, राजेश गोंड, शारदा प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सड़क हादसे में युवक गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर

कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के खड्डा तहसील में गुरुवार शाम करीब 5 बजे जिंदा छपरा- मिश्रौली मार्ग पर एक सड़क हादसे में भुजौली बाजार टोला निवासी अजय (पुत्र महेंद्र गोंड) गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि अजय गांव के एक बुजुर्ग के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए पनियहवा गए थे और वहां से अकेले बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है। दुर्घटना में अजय के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अजय पेशे से ड्राइवर हैं और दूसरों की गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी शादी लगभग दो वर्ष पहले हुई थी।

लिटिल वंडर्स पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों ने बांधा समा

कुशीनगर।

कसानगंज विकासखंड के बौलियां स्थित लिटिल वंडर्स पब्लिक स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रबंधक मैना देवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को उत्साह और उमंग से भर दिया।

कार्यक्रम में छात्रा निशा, प्रियंका, पूनम, प्रीति, सरिता और शिवांगी ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी, वहीं मीरा, सुनीता, किरण और मालती सहित अन्य छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की। विद्यालय के डायरेक्टर अनूप सिंह ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की।

प्रधानाचार्य पी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास और मंच कौशल को विकसित करती हैं। कार्यक्रम के अंत में रविंद्र सिंह ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान गौतम सिंह, अरुण गुप्ता, अमरनाथ सिंह, अभिषेक वर्मा, कमल किशोर मिश्रा, संतोष यादव, लाल बहादुर सिंह, श्याम सिंह, सूरज सिंह, सर्वेश सिंह, सुशील दुबे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को लेकर डीएम के सख्त निर्देश, पंजीकरण अनिवार्य

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार जनपद के समस्त विक्रय अधिकारी (एलपीजी) को वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव के पत्र दिनांक 24 मार्च 2026 तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को एलपीजी संकट से पूर्व की स्थिति के सापेक्ष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा। इसमें अतिरिक्त आवंटन प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण एवं डेयरी इकाइयों, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन, सामुदायिक रसोई तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल श्रेणी को दिया जाएगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक गैस प्राप्त करने से पूर्व संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ओएमसी द्वारा उपभोक्ताओं के एलपीजी उपभोग का पूरा विवरण अपने डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र में संचालित सिटी गैस वितरण इकाई के साथ पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना भी आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने सभी विक्रय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2025 तथा जनवरी व फरवरी 2026 के दौरान संबंधित संस्थानों एवं उद्योगों को उपलब्ध कराए गए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की संख्या का विवरण तत्काल उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। साथ ही निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्वयंभू विश्वगुरु की असफलताओं के कारण टूटा हुआ देश ब्रोकर राष्ट्र बन गया - कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने पश्चिम एशिया संघर्ष में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिए गए दलाल राष्ट्र के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वयंभू विश्वगुरु की कूटनीति और बयानबाजों की विफलताओं ने टूटे हुए देश को ब्रोकर राष्ट्र में बदल दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि स्थापित और अत्यंत अनुभवी कहे जाने वाले विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए बातचीत में पाकिस्तान के मध्यस्थ एवं पहलकर्ता के रूप में उभरने से भारत को हुई भारी शर्मिंदगी और क्षेत्रीय कूटनीति को लगे झटके को ढकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, यह वास्तव में घोर आपत्तिजनक है कि पाकिस्तान को इस भूमिका के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। पाकिस्तान वही देश है जिसकी सरकारी व्यवस्था ने चार दशकों से अधिक समय तक भारत और अन्य देशों में आतंकवाद को प्रायोजित और संचालित किया है, ओसामा बिन लादेन और अन्य खतरनाक वैश्विक आतंकवादियों को दशकों तक पनाह दी, परमाणु अप्रसार कानूनों का घोर उल्लंघन कर अन्य देशों को परमाणु क्षमता हासिल करने में मदद की। उन्होंने कहा, (पाकिस्तानी वैज्ञानिक) ए. क्यू. खान नेटवर्क की भूमिका का दस्तावेजों में जिक्र किया गया है और (पाकिस्तान के) तत्कालीन राष्ट्रपति (परवेज) मुशर्रफ ने भी स्वयं इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अस्पतालों और असैन्य ठिकानों पर बेरहमी से बमबारी की और विभिन्न प्रांतों-बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में अपने ही नागरिकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाना प्रधानमंत्री की उस कूटनीति की वास्तविकता और उसके तौर-तरीके दोनों पर एक बेहद गंभीर प्रश्न है, जो बड़े-बड़े दावों और वाक्पटुता से चिह्नित रही है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया था क्योंकि डॉ. मनमोहन सिंह की तत्कालीन केंद्र सरकार दुनिया को पाकिस्तान की साजिशपूर्ण भूमिका से अवगत कराने में सफल रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और जहरीले बयानों के बाद भी हम पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करने में असफल रहे। उल्टा, वह (मुनीर) और अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आए और 10 मई 2025 के बाद तो यह साफ हो गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (अमेरिका के) राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप और उनकी टीम के पसंदीदा बन चुके हैं।

बंगाल में टीएमसी -बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 20 जख्मी

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इसमें 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यह घटना बासंती (एससी) विधानसभा सीट में हुई है। यहां 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण में मतदान होना है। उधर, चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले एक महीने में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे लोगों से 17.44 करोड़ कैश जब्त किया है।

ममता बनर्जी बोलीं- न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम हटेंगे, टीएमसी करेगी उनकी मदद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन मतदाताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगी, जिनके नाम चल रही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बर्दवान जिले के पांडवेश्वर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जिन वोटरों के नाम न्यायिक प्रक्रिया में हटा दिए जाएंगे, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कानूनी मदद दी जाएगी। हम उनके लिए वकीलों का इंतजाम करेंगे। उनकी यह घोषणा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की उस जानकारी के एक दिन बाद आई है, जिसमें बुधवार शाम को बताया गया था कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजे गए 60 लाख मामलों में से, मंगलवार रात तक 32 लाख मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और उन 32 लाख मामलों में से लगभग 40 प्रतिशत मामले ऐसे पाए गए जिन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया से हटाए गए इन वोटरों को, इस काम के लिए बनाए गए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों में से किसी एक के पास जाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए खास पहल करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, वे हम पर चाहे जैसे भी हमले करें, लेकिन आखिर में जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। इस प्रक्रिया में महिलाओं को आगे बढ़कर मुख्य भूमिका निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा चुनावी धांधली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा, वे लॉकडाउन का सहारा भी ले सकते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। लेकिन हमें लड़ना आता है। अगर हम महामारी के दौरान लड़ पाए थे, तो हम अब भी लड़ पाएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों को कुरुक्षेत्र का महायुद्ध भी बताया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पांडवों का और भाजपा कौरवों का प्रतिनिधित्व करती है । उन्होंने एलपीजी बुकिंग के नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा, कल मैंने सुना कि गैस बुकिंग की अवधि घटाकर 25 दिन कर दी गई है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं; मुझे उन पर भरोसा नहीं है। आप 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं कर सकते। अगर लोगों की गैस खत्म हो गई तो वे क्या करेंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का करेंगे उद्घाटन

नोएडा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इसका उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक मील का पत्थर है। बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च, 2026 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वह पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे गौतमबुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा हवाईअड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। बयान में कहा गया कि दिल्ली और नोएडा हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे जिससे भीड़भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली-एनसीआर को दुनिया के प्रमुख विमानन केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 11,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। आरंभ में इस हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता प्रति वर्ष एक करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। इसके पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद इसे बढ़ाकर प्रति वर्ष सात करोड़ यात्रियों तक किया जा सकता है।

मिडिल ईस्ट संकट : पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक

ईंधन सुरक्षा को लेकर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली ।

मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे. पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है. इस बैठक का मुख्य जोर टीम इंडिया की भावना के साथ सभी प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा. इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. पीएम मोदी की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी. पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है. केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा करेगी. इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है. इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने विपक्ष और सरकार की तरफ से दिए गए सभी सुझावों को डिटेल में सुना है, सभी सवाल और सभी कन्फ्यूजन, जो कुछ भी था, सरकार ने उन सभी को साफ-साफ समझाया और विपक्ष ने मीटिंग के आखिर में कहा, जो बहुत

'संसद में कहा था- आने वाला समय परीक्षा लेगा, राज्य-केंद्र को मिलकर काम करना होगा

जरूरी है कि वे इस ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में हम सभी को एक साथ खड़ा होना होगा. किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि कई सदस्य होर्मुज स्ट्रेट से गैस और पेट्रोलियम सप्लाई की डिटेल्स जानना चाहते थे. वे सभी इस बात से संतुष्ट थे कि भारत पहले ही चार जहाज लाने में सफल रहा. इसलिए विपक्षी सदस्य सरकार की कोशिशों से संतुष्ट थे.

आंध्र प्रदेश-डंपर से टकराकर बस में आग, 13 जिंदा जले-22 घायल

3 घंटे में आग पर काबू पाया गया, पीएम मोदी ने जताया शोक

मरकापुरम।

आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में रायवरम के पास गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ। एक प्राइवेट ट्रैवल बस और डंपर में टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस में आग लग गई। बस में सवार 13 यात्री जिंदा जल गए। हालांकि पहले पुलिस की तरफ से पहले 14 मौतों की जानकारी दी गई थी। बाद में सीएम ऑफिस ने मौत का आंकड़े में आफिशियल कंफर्मेशन दिया। अधिकारियों ने बताया कि हरिकृष्णा ट्रैवल्स की बस तेलंगाना के निर्मल से नेल्लोर जा रही थी। हादसा सुबह 6:00 बजे के करीब हुआ। आग पर करीब तीन घंटे में काबू पाया गया। मरकापुरम के एसपी वी हर्षवर्धन राजू ने कहा, डंपर ड्राइवर समेत 22 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 35 यात्री सवार थे। घटना की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों की मौत पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में हुए भीषण बस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये व घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है।

बांग्लादेश में बस नदी में गिरी, 26 की मौत

ढाका । बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस दौलतदिया घाट पर फेरी (बड़ी नाव) में चढ़ते समय पद्मा नदी में गिर गई। फायर सर्विस के मुताबिक, 23 शव बस के अंदर से निकाले गए, जिनमें 11 महिलाएं, 8 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जिंदा बचाया गया था, लेकिन उनमें से 3 लोगों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। कुछ लोगों की तलाश जारी है। वहीं, 22 मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसा बुधवार शाम को हुआ। तब सिर्फ 2 लोगों की मौत की खबर आई थी। बांग्लादेश में बसों और गाड़ियों को नदी पार कराने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। यह एक बड़ी नाव या जहाज जैसा होता है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और जांच के आदेश दिए।

ईरान ने भारत समेत 5 देशों को होर्मुज से गुजरने की दी अनुमति , बोला-सिर्फ मित्र देशों' के लिए खुला रास्ता

नई दिल्ली । ईरान ने भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान एवं इराक जैसे मित्र देशों को वाणिज्यिक नौवहन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यह जानकारी दी। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिए जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा नौवहन मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) का परिवहन होता है। पश्चिम एशिया, भारत की ऊर्जा खरीद का एक प्रमुख स्रोत रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, अराघची ने कहा, हमने कुछ ऐसे देशों को (होर्मुज जलडमरूमध्य से) गुजरने की अनुमति दी है जिन्हें हम मित्र मानते हैं। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को आवागमन की अनुमति दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने साथ ही स्पष्ट किया कि ईरान के शत्रुओं से जुड़े पोतों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम युद्ध की स्थिति में हैं। यह क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बना हुआ है और हमारे दुश्मनों एवं उनके सहयोगियों के पोतों को इससे गुजरने देने का कोई कारण नहीं है लेकिन यह अन्य देशों के लिए खुला है। होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक नौवहन में व्यवधान को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वह जलमार्ग को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले कुछ सप्ताह में भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त कराने और होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने पर केंद्रित कूटनीतिक प्रयास किए हैं। भारत का मानना है कि यदि इस नौवहन मार्ग पर अवरोध जारी रहा तो भारत सहित कई देशों की ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

पेट्रोल, डीजल पर सरकार का बड़ा बयान, कहा- राशनिंग न करें, देश के पास है 60 दिन का भंडार

नई दिल्ली । सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के पास लगभग 60 दिनों का ईंधन भंडार है और पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस (एलपीजी) की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ईंधन की कमी की खबरों को जानबूझकर फैलाया गया गलत सूचना अभियान बताया, जिसका उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक है और वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पेट्रोल या डीजल की कोई राशनिंग नहीं की जा रही है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन के मामले में दुनिया में चौथे और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक भारत, घरेलू ईंधन की उपलब्धता को संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित करता है और 150 से अधिक देशों को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करता है। बयान के अनुसार, प्रत्येक भारतीय रिफाइनरी (जो कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में परिवर्तित करती है) 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चल रही है। अगले 60 दिन के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। इसमें कहा गया है कि भारत के पास कुल 74 दिन की कच्चे तेल और ईंधन भंडारण क्षमता है। मंत्रालय ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के 27वें दिन भी, हमारे पास अभी लगभग 60 दिन का वास्तविक भंडार (जिसमें कच्चे तेल का भंडार, उत्पाद भंडार और रणनीतिक भंडारण शामिल है) है। बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर चाहे जो भी हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक की जरूरतों को पूरा करने लिए लगभग दो महीने की स्थिर आपूर्ति उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि दो माह की कच्चे तेल की खरीद पहले ही सुनिश्चित होने की वजह से अगले कुछ माह तक भारत के लिए समस्या नहीं है और ऐसी आपूर्ति की स्थिति में रणनीतिक भंडारण में रखी मात्रा का महत्व गौण हो जाता है।

ईरान ने हमें तेल के 10 टैंकर दिए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- इन पर लगा था पाकिस्तानी झंडा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (26 मार्च 2026) को कहा कि ईरान ने उन्हें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किया है. ट्रंप के अनुसार 8 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार चुका है और सभी पर पाकिस्तान के झंडे लगे थे. उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध समाप्त करने की गंभीरता को दिखाते हुए ऐसा किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करना होगा या फिर हमले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा, ईरान के पास अब मौका है कि वह अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए त्याग दे और एक नए रास्ते पर आगे बढ़े. हम देखेंगे कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके लिए सबसे बुरा सपना साबित होंगे. फिलहाल हम हमला जारी रखेंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण करना अमेरिका के लिए एक विकल्प है. ट्रंप ने पूछा गया, क्या ईरान का समाधान वेनेजुएला जैसा हो सकता है, जहां यूएस ने निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ तेल और अन्य मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया. इस पर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के साथ काम करने में हमें काफी सफलता मिली है. हमने अरबों-खरबों डॉलर कमाए हैं. वैसे, वेनेजुएला इस समय अपने देश के इतिहास में सबसे बेहतर स्थिति में है.

मध्यप्रदेश-सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस पलटी, 10 मौतें

छिंदवाड़ा । मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पिकअप से टक्कर के बाद एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में कुछ यात्रियों के हाथ कटने और कई के सिर फूटने जैसी गंभीर चोटें सामने आई हैं।

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मौतों की पुष्टि की है। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने सहायता राशि की घोषणा भी की है। पुलिस के अनुसार, घटना शाम करीब साढ़े 6 बजे उमरानाला क्षेत्र में हुई। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे और यह छिंदवाड़ा से उमरानाला की ओर जा रही थी। जानकारी मिली है कि बस में सवार अधिकांश लोग चौरई तहसील में आयोजित हितग्राही सम्मेलन से लौट रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए थे। फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को

*30 से ज्यादा घायल; महिला और बच्चे का हाथ कटकर अलग, छिंदवाड़ा के सिमरिया में हादसा

प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

क्या बोले कलेक्टर?

कलेक्टर ने कहा कि बस में 47

यात्री सवार थे। ये बस छिंदवाड़ा की तरफ से आ रही थी। सिमरिया के पास बस एक वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी लहसुन से लदी एक पिकअप वाहन की आमने-सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पांच की हालत गंभीर बनी हुई है और 10 मौतों की जानकारी है।

सीएम ने सहायता राशि की घोषणा की

आज शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर हुई सड़क दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता हूं। मैंने संबंधित अधिकारियों को घायलों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर से डॉक्टर्स के दल छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह जी को भी अपने कार्यक्रम परिवर्तित कर छिंदवाड़ा पहुंचने के लिए निर्देशित किया है। मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी घायलों के उपचार की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

कमलनाथ ने भी जताया दुख

छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु और घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था के साथ ही उन्हें भी पर्याप्त अनुग्रह राशि दी जाए।